



संक्षिप्त समाचार

सरकार ईमानदारी के साथ कर रही अपना काम: सीएम संवाददाता देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि सरकार ईमानदारी के साथ अपना काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 2017 के चुनाव में जनता से किए 85 फीसद वादों को पूरा किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार लगातार कार्य कर रही है। भ्रष्टाचार के मामले में 5 पीसीएस के अलावा दो अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर उन्हें निलंबित किया गया। उन्होंने कहा कि सरकार समाज के सभी वर्गों के लिए कार्य कर रही है। औद्योगिक व किसी के क्षेत्र में आगे बढ़कर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ की हड्डी है।

लव जेहादियों का फूका पुतला संवाददाता देहरादून। हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी द्वारा लैंसडाउन चौक पर लव जेहादियों का पुतला दहन कर दोषियों को सख्त सजा दिलाये जाने की मांग की गई। यहां हिंदू जागरण मंच युवा वाहिनी के कार्यकर्ता लैंसडाउन चौक पर इकट्ठा हुए और वहां पर लव जेहादियों के खिलाफ जमकर प्रदर्शन कर पुतला फूका। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड में दिन-प्रतिदिन लव जिहाद की घटना बढ़ती जा रही हैं हिंदू जागरण मंच का लव जिहाद विषय पर जागरूकता अभियान कई वर्षों से चला आ रहा है। प्लास्टिक लाओ मॉस्क पाओ अभियान की शुरुआत

संवाददाता देहरादून। नगर निगम देहरादून, यूएनडीपी एवं एचडीएफसी बैंक के संयुक्त प्रयास से वेस्ट वारियर्स संस्था द्वारा प्लास्टिक लाओ मॉस्क पाओ अभियान की शुरुआत नगर निगम कार्यालय से नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय के द्वारा औपचारिक शुरुआत की गयी। नगर आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने इस कार्यक्रम को एक अनूठा प्रयास बताते हुए कहा कि यह अभियान सभी को गीला कचरे से सूखा कचरा एवम प्लास्टिक को अलग अलग करने को प्रेरित करेगा, जोकि शहर में बढ़ रहे मिश्रित कचरे के दुष्प्रभाव को भी कम करने में मदद करेगा। 50 लाख के लैपटॉप लेकर फरार हुआ झाइवर, व्हील्सआई के मदद से हुए बरामद

संवाददाता देहरादून। 27 अक्टूबर को देहरादून ऑफिस से गाडी नंबर यूके07सीबी7834 में कंप्यूटर का सामान और लैपटॉप लेकर झाइवर और हेलपर रुड़की, हरिद्वार और ऋषिकेश डिलीवरी करने निकले थे। रुड़की में माल देने के बाद जब हेलपर बाहर आया तो ट्रक गायब था। वह 42 लैपटॉप लेकर झाइवर फरार था। व्हील्सआई और रुड़की पुलिस की मदद से 42 में से 40 लैपटॉप दिल्ली से सही सलामत मिल गए।

पात्र लोगों को समय से नहीं मिल रहा योजनाओं का लाभ

आरोप

संवाददाता

देहरादून। दलित समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस गुरुवार को गांधी पार्क में धरना देगी। धरना कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आयोजित किया जा रहा है। धरने प्रदेश कांग्रेस के अलावा महानगर कांग्रेस, महिला कांग्रेस, युवा, भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन, सेवादल के कार्यकर्ता भाग लेंगे।

मंगलवार को कांग्रेस अनुसूचित जाति जनजाति विभाग के अध्यक्ष व पूर्व विधायक राजकुमार ने राजपुर रोड स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में कहा। उन्होंने आरोप लगाए की देशभर में दलित समाज पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं जिसका कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर विरोध करेगी। उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी के अनुसूचित जाति जनजाति

■ दलित समाज पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कांग्रेस गांधी पार्क में देगी धरना



विभाग के प्रदेश अध्यक्ष व पूर्व विधायक राजकुमार ने कहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति के कल्याणार्थ कई योजनाएं पूर्व सरकार द्वारा चलाई गयी थी, जिनका वर्तमान में क्रियान्वयन सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है, उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र लोगों को समय पर

नहीं मिल पा रहा है, जिससे अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों में रोष है।

कांग्रेस भवन में पत्रकारों से रुबरु होते हुए उन्होंने कहा कि समाज कल्याण विभाग द्वारा छात्रवृत्ति समय पर न मिलने के कारण छात्रों को शिक्षण संस्थानों व विद्यालयों से निकाला जा रहा है,

इस कारण छात्रों का भविष्य भी अंधकारमय हो रहा है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी विभाग की है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019-2020 की अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति के छात्र-छात्राओं को वर्तमान तक छात्रवृत्ति नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि जिससे विद्यार्थियों को पठन-पाठन में कठिनाई हो रही है। इसमें शीघ्र छात्रवृत्ति जारी की जाये। उन्होंने कहा कि प्राइमरी स्कूल में कक्षा 01 से 05 तक रुपये 600 तथा कक्षा 06 से कक्षा 08 तक रुपये 900 प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, जो कि काफी कम है, इसे बढ़ाये जाने की आवश्यकता है और सरकार को इस दिशा में पहल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति के हितार्थ केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं स्वीकृत हैं, उनका व्यापक स्तर पर प्रचार प्रसार किया जाये इसमें समाचार पत्रों के साथ साथ मुख्य-मुख्य स्थानों पर होर्डिंग लगवाया जाये।

उत्तराखंड में न दोहराएं आंध्र प्रदेश की घटना

चेतावनी

■ बच्चा संक्रमित हुआ तो एसोसिएशन स्कूलों में तालाबंदी को बाध्य होगी

देहरादून। संवाददाता

उत्तराखंड सरकार द्वारा स्कूलों को खोले जाने को लेकर नेशनल एसोसिएशन फॉर पैरेंट्स एंड स्टूडेंट्स राइट्स के नेहरू कोलोनी स्थित राष्ट्रीय कार्यालय में बैठक आहूत की गई जिसमें कोरोना वायरस कोविड 19 के बढ़ते संक्रमण व बच्चों की शिक्षा के साथ ही उनकी सुरक्षा को लेकर अभिभावक चिंतित नजर आए।

इस अवसर पर जैसा कि ज्ञात हो कि पूर्व में भी एनएपीएसआर



द्वारा अभी स्कूल खोले जाने को लेकर आपत्ति जाहिर करते हुए मानवाधिकार का दरवाजा खटखटाते हुए अपील करी थी कि उत्तराखंड में न दोहराएं आंध्र प्रदेश की घटना अपील में यह भी कहा गया है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने लॉक डाउन 05 के चलते स्कूलों को खोले जाने का निर्णय राज्य

सरकारों पर छोड़ा है।

उत्तराखंड सरकार ने अभिभावकों व स्कूल संचालकों की सहमति से स्कूलों को खोलने का निर्णय लिया है वह सरकार की ओर से लिया गया एक सरहानीय कदम है किन्तु 10वीं और 12वीं के की कक्षाओं को खोलने का निर्णय भी अभी ठीक नहीं है। इस अवसर पर

एसोसिएशन के अध्यक्ष आरिफ खान का कहना है कि जिस प्रकार से सरकार ने निजी स्कूलों की जिद और अपने राजनीतिक प्रभाव के चलते स्कूल खोले हैं और रानीखेत में पहले ही दिन 12वीं के छात्र का संक्रमित पाया जाना और स्कूल को पुनः तीन दिन के लिए बन्द किया जाना इस बात को चेतावनी है कि खतरा अभी टला नहीं है।

इस प्रकार के बच्चे से यदि और बच्चे भी संक्रमित होते हैं तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी किसकी होगी क्योंकि स्कूल अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं और अभिभावकों के लाख मना करने के बावजूद भी सरकार ने स्कूलों को खोलने का जो निर्णय लिया है तो उसके लिए छात्रों के संक्रमित होने पर जवाबदेही भी सरकार की होगी।

शिफन कोर्ट के 80 परिवारों का किया जाये विस्थापन मसूरी। मसूरी के शिफन कोर्ट के 80 पहाड़ी परिवारों के विस्थापन किये जाने व शहीद स्थल को न तोड़े जाने की मांग को लेकर चिन्हित राज्य आंदोलनकारी संयुक्त समिति ने जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया। समिति के केन्द्रीय संयोजक व पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री मनीष नागपाल के नेतृत्व में आंदोलनकारी जिलाधिकारी कार्यालय में इकट्ठा हुए और वहां पर जिला प्रशासन के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन प्रेषित किया गया। ज्ञापन में कहा गया है कि विगत दिनों मसूरी के शिफन कोर्ट में रह रहे लगभग 80 पहाड़ी परिवारों को अतिक्रमण हटाने के नाम पर बेघर कर दिया गया था और केवल रोपवे निर्माण के लिए इतने लोगों को हटाया जाना ठीक नहीं है यह लोग अंग्रेजों के जमाने से वहां पर रह रहे थे। केवल विकास के नाम पर जनता का उत्पीड़न ठीक नहीं होता है प्रशासन ने इनको न्यायालय की आड़ लेकर बेघर किया अगर यह चाहते तो जैसे देहरादून की बस्तियों को न्यायालय न हटाने का आदेश दिया था पर राज्य सरकार ने उन्हें अध्यादेश लाकर बचा लिया और कहीं पर उच्चतम न्यायालय की शरण ली परंतु यहां पर सरकार ने ऐसा नहीं किया।

मंडल प्रशिक्षण वर्ग का द्वितीय सत्र का समापन

संवाददाता देहरादून। भारतीय जनता पार्टी जी एम एस मंडल कैंट विधानसभा द्वारा आयोजित दो दिवसीय मंडल प्रशिक्षण वर्ग का द्वितीय सत्र में रविंद्र कटारिया राज्यमंत्री पशुपालन एवं भेड़ ने कहा कि पिछले छह सालों में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा किए गए सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और कहा कि सरकार व्यापक स्तर पर विकास कार्य को अंजाम दे रही है। देवेन्द्र पाल ने सोशल मीडिया व उसका उपयोग एवं व्यक्ति विकास के बारे में जानकारी दें। इस अवसर पर विधायक हरबंस कपूर की गरिमामय उपस्थिति में बबलू बंसल मंडल अध्यक्ष की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर मयंक गुप्ता द्वारा आज के भारत की वैचारिक मुख्य धारा एवं हमारी विचारधारा के बारे में जानकारी दी गई। इस अवसर पर सत्र में मंडल की पूर्ण जानकारी प्रदान की गई।

In a Digital World Why To wait for a Howker

Visit Us at <http://app.page3news.co.in>

Supporting Devices

All Apple Touch Phones & Tablets
All Android Touch Phones & Tablets
All Window & BlackBerry Touch Phones 10+

Read News
Watch News Channel

Scan This Code

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक प्रदीप चौधरी द्वारा एल.के. प्रिंटर्स, 74/9, आराधर, देहरादून से मुद्रित व जाखन जोहड़ी रोड, पी.ओ.-राजपुर, देहरादून से प्रकाशित। संपादक: प्रदीप चौधरी

सिटी कार्यालय: शिवम मार्केट, द्वितीय तल दर्शनलाल चौक, देहरादून। फ़ैक्स नं०- 0135-2650558 (M) 9319700701 pagethreedaily@gmail.com आर.एन.आई.नं० UTTHIN\2005\15735 सभी विवादों का न्याय क्षेत्र देहरादून ही मान्य होगा।